Establishment of a separate bench of the Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh

श्री के. सी. त्यागी (बिहार) : सर, देश की 10 करोड़ आबादी की तकलीफ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से लगातार यह मांग चल रही है कि वहां पर हाई कोर्ट की एक बैंच की स्थापना की जाए। जसवंत सिंह आयोग बना, उसने रिकमण्डेशन दी कि हां, बननी चाहिए। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि बननी चाहिए। जो संविधान के निर्माता थे डा. अम्बेडकर और उनके सहयोगी भी थे, उन सबने लिखा कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सस्ता न्याय मिलना चाहिए और सबके द्वार पर जाना चाहिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद लगभग 700 किलोमीटर पड़ता है। एक गरीब किसान को, मजदूर को अपनी बात कहने के लिए, वहां जाने के लिए कितना खर्चा करना होता होगा, कितनी मुसीबतें होती होंगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना के साथी बतला रहे थे, यह महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहले हाई कोर्ट की बैंच मांगी थी, आपने पूरा राज्य दिया लेकिन हाई कोर्ट की बैंच नहीं मानी। अकाली दल के लोग हैं, उन्होंने चाहा कि गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस चल जाए और वेटिकन सिटी की तरह से शराब की दुकानें न हों। आपने देश के प्रधान मंत्री की जान दे दी, लेकिन आपने अमृतसर को वेटिकन सिटी का दर्जा नहीं दिया। बंटवारे के टाइम पर मुस्लिम लीग ने दो विभाग मांगें, आपने पाकिस्तान दे दिया लेकिन दो विभाग देने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तो यह जो आपका माइंडसैट है, यह बहुत खतरनाक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में गंभीरता से बात की जाए और यहां से लेकर वहां तक सभी पार्टियों के नेताओं की राय जानी जाए, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता लगे कि इसके बारे में सब की क्या राय है। ये धरने पर जाएंगे, कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। फिर दूसरा धरना होगा, उसके भी साथ हैं। तीसरा होगा, कहीं भी हो। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच नहीं बनती है तो मैं चाहता हूं कि जेटली जी के राज्य में दिल्ली के अंदर इन 15 जिलों को जोड़ करके हमें कोई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। वरना मैं इस सदन में चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूफान उठेगा, आपका पानी बंद होगा, आपका दूध बंद होगा, आपका राशन बंद होगा और पूरी दिल्ली को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग घेरेंगे, तब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोगे, लेकिन बैंच नहीं दोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां सभी दलों के नेता बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, मिश्रा जी से भी मैंने बात की थी। जो उपनेता हैं, वे निजी बातचीत में तो बड़ी अच्छी बात करेंगे हाथ जोड़ करके, लेकिन जब मौका आएगा तो उस वक्त हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इनकी चुप्पी तुड़वाने का प्रयास होना चाहिए। दो लोगों की चुप्पी बड़ी खतरनाक है। एक तो डिप्टी एल.ओ.पी. की और एक मिश्रा जी की। मैं चाहता हूं कि इसमें इनका इंटरवेंशन भी औरों की तरह से जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : पहले त्यागी जी उत्तर प्रदेश से एम.पी. बन कर आएं, तब हम उनकी बात सुनेंगे।

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री मोहम्मद शफी (जम्मू और कश्मीर) : महोदय, मैं भी इसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

† **جناب محمد شفیع (جموں و کشمیر)** : مہودے، میں بھی اس کے ساتھ سمبدّ کرتا ہوں۔

Hike in the prices of petrol and diesel for the sixth time in this year

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, when the Parliament is in session, when we are discussing very seriously the issue of rise in prices, its effect on the people, particularly on the farmers, and the Short Duration Discussion on this issue is pending, at that particular time price hike of diesel and petrol has been announced by the UPA-II Government. Sir, this is not the first time that it is happening. Since the UPA-II Government has come into existence, we have seen many such examples. I remember, on one occasion, just 12 hours before the Parliament session began, the prices of petrol were increased. Here, the increase in the price of petrol is of Rs. 2.35 per litre. This is the sixth increase in the price of petrol in the last three months. The price of diesel has been increased on the monthly basis of 50 paise per litre and a steeper increase is expected after the Parliament session is over. The prices of kerosene and gas will be increased and it will seriously affect all sections of people. Unable to check the falling value of the Rupee, the UPA Government is resorting to successive increases in the fuel prices. This will only add to the burden of the people by growing inflation and rising prices of all commodities. Sir, it is a matter of deep concern. This Government is responsible for the increasing miseries of the people. Prices are increasing and according to the Government, the number of BPL people is coming down. After the UPA-II Government came into existence, decontrolling of petrol started. On diesel, they have taken an in-principle decision. Partial decontrol has been announced since January.

When it comes to public transport, it has been mentioned here in Parliament, diesel price has been raised by 50 paise per litre per month. We hereby demand to scrap that Ordinance or that Government Order; it will be helpful to the people. What will happen if you include the local sales tax and VAT to it? It will definitely differ from city to city. It will further burden ..

†Transliteration in Urdu Script.